वित्तीय समावेशन

समस्त जनसंख्या, विशेष रूप से अल्पआय तथा कमजोर एवं निर्धन लोगों को वहनीय लागत पर पारदर्शी ढंग से साख सुविधाएँ अथवा बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

ऐसे लोग जो बैंकिंग सेवाओं या साख सुविधाओं से वंचित होने के कारण गाँवों में साहूकारों, महाजनों आदि से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं और अंतत: ऋण जाल में फंस जाते हैं।

1. बैंकिंग – सेविंग, ATM
2. क्रेडिट – ऋण प्राप्त
3. निवेश – Pension Plan
4. बीमा – LIC, GI.

वित्तीय समावेशन हेतु किये गये प्रयास —

- बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- PSL
- स्वयं सहायता समूह की शुरुआत
- स्वाभिमान योजना (2011; 2000 से अधिक आबादी वाले 74,000 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाई।).
- Zero-Balance account (2012)
- जन-धन योजना (28 अगस्त, 2014).

वित्तीय समावेशन के लिए अनिवार्यताएँ —

i) दूर-दराज के पिछड़े इलाकों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना।

ii) लोगों को बैंकिंग प्रणाली के लाभ से परिचित कराना ताकि अधिक से अधिक लोगों का खाता खोलने हेतु प्रेरित किया जा सकें।

iii) न्यूनतम लागत पर ऋण प्रदान करना, ताकि ऋण जाल में न फंसे।

iv) बैंकिंग प्रणाली में ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो जनसंख्या की विविधता हो।

वित्तीय साक्षरता —

इससे आशय उन शब्दों से है जिनका सामना किसी निवेशक को मुद्रा बाजार में प्रवेश करते समय करना पड़ता है। जैसे — किस प्रकार धन का निवेश, व्यवस्था या किसी की सहायता के लिये दान किया जाए आदि ज्ञान से है।

अधिकांश भारतीय मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर जैसी प्रमुख धारणाओं को नहीं समझते। यही कारण है कि बहुत से लोग, विशेषकर निर्धन तथा महिलाएँ बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रह जाते हैं।

"विकास वह है जो स्वतंत्रता दिलाता है।"

— प्रो. अमर्त्य सेन

संवृद्धि (GROWTH)	विकास (DEVELOPMENT)
i) यह मात्रात्मक होती है।	i) यह गुणात्मक होती है।
ii) यह राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में होने वाले प्रदर्शन को प्रभावित करती है।	ii) यह जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है।

कोई संदेह नहीं है, कि जीवन की अच्छी गुणवत्ता के लिए आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं, अर्थात जीवन की अच्छी गुणवत्ता को केवल राष्ट्रीय आय द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

आय के साथ-साथ अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कि भी आवश्यकता होती है। विकास में इन सब आयामों को भी ध्यान में रखा जाता है।

विकास के मापक —

गुणात्मक अवधारणा होने के कारण इसे गणितीय रूप से मापा नहीं जा सकता लेकिन इसमें होने वाले परिवर्तन का पता लगाने के लिए UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) - 1965 द्वारा 1990 से एक मानव विकास सूचकांक HDI शुरु किया गया।

HDI Ranki.
2014-1?
2015-13